PRGI No. UPHIN/25/A1697

# गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 055
दि. 24.06.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

**केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चचाओं के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति की यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई है।**

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चचाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह पीएम मोदी की राष्ट्रपति से यह मुलाकात पद्म पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में हुई है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर मोदी कैबिनेट में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति की इस बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद में किसी संभावित बदलाव या फेरबदल को लेकर भी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिर भी, इस मुलाकात को संभावित केंद्रीय कैबिनेट विस्तार या फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। जिससे राजनीतिक हलकों में चचाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल सभी की नजरें सरकार की ओर से आने वाले किसी आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं।

**राष्ट्रपति कार्यालय ने शेयर की तस्वीर**

राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। पोस्ट में कहा गया, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।'

**क्यों अहम है यह मुलाकात?**

पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह के ठीक बाद हुई यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक हलकों में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा जोरों पर है।

**मोदी सरकार के मंत्री ने दिया इस्तीफा**

इससे पहले दिन में, केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कुरियन (65) अल्पसंख्यक मामलों के साथ-साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू ने कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

कुरियन ने 9 जून 2024 को बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री शपथ ली थी। 11 जून को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। 65 वर्षीय कुरियन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वे 1980 में पार्टी बनने के वक्त से ही सदस्य रहे हैं। उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियां निभाईं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने केरल में पार्टी के विस्तार के लिए काम किया।

**मोदी 3.0 में मंत्री बने थे कुरियन**

जार्ज कुरियन कोट्टायम के रहने वाले हैं। 2024 में मोदी सरकार 3.0 में उन्हें मंत्री बनाया गया था, जो केरल से पार्टी की ईसाई आउटरीच रणनीति का हिस्सा था। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कंजिराप्पल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में उतरे कुरियन चुनाव हार गए थे।

## गैस प्लांट हादसे में 12 भारतीयों की मौतः प्रधानमंत्री मोदी को कतर के अमीर ने किया फोन, जानिए क्या हुई बात

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, कतर के रास लफान गैस प्लांट में तकनीकी खराबी से हुए विस्फोट में 12 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद कतर के अमीर ने पीएम मोदी को फोन कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और संकट की इस घड़ी में दोनों देशों ने आपसी एकजुटता दोहराई है।

सोमवार को कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी के एक बड़े गैस प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद देश में शोक की लहर है।

इस दुखद घड़ी में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फोन कॉल के लिए कतर के अमीर का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों का दर्द साझा किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। भारत और कतर ने जोर दिया कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश इस मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।

## इथियोपिया के संसदीय चुनाव में अबी अहमद की प्रचंड जीत, पीएम मोदी ने 'दोस्त' को कुछ यूं दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और उनकी पार्टी प्रॉस्पेरिटी पार्टी को संसदीय चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच ऐतिहासिक, बहुआयामी और गहरे संबंध हैं, जिन्हें भारत बेहद महत्व देता है।

पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'उन्हें पिछले वर्ष की इथियोपिया यात्रा की यादें आज भी ताजा हैं। उन्होंने आगे काह, वह भारत और इथियोपिया के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री अबी अहमद

के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं।

इन दिनों इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा टैडेसे ब्रिक्स देशों के NSA की बैठक में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने सोमवार को 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की बैठक के दौरान इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा (एनआईएसएस) के विश्लेषण विभाग के कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा टैडेसे से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत-इथियोपिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत तथा गहरा बनाने के लिए सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की।"

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 और 17 दिसंबर 2025 को अपनी पहली राजकीय द्विपक्षीय यात्रा के लिए इथियोपिया गए थे। अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ था। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर कई समझौते किए गए थे।

## प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने समकालीन वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में इस समूह के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को और गहरा करने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

## अरविंद केजरीवाल का राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा हमला, चंपत राय के इस्तीफे की मांग!

(जीएनएस)।

अयोध्या के भव्य राम मंदिर के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े चंदे का विवाद एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में केजरीवाल ने मंदिर के पैसों में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

केजरीवाल का यह ताजा हमला ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर के चंदे और ट्रस्ट की भूमिका को लेकर जनता के बीच विभिन्न प्रकार की चचाएं चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि देश भर के राम भक्तों के मन में मंदिर प्रबंधन को लेकर कई अनुत्तरित सवाल हैं। इन सवालों के जवाब देना और जनता के सामने पूरी पारदर्शिता रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

इस पूरे मामले में जनता की आस्था का हवाला देते हुए आप नेता ने इसे विश्वासघात करार दिया। उनका कहना है कि करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा से जो पैसा मंदिर के लिए दिया था, उसके साथ किसी भी तरह का विश्वासघात स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को अब जनता की अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

केजरीवाल ने अपने वीडियो संदेश में सीधे तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि जब पूरे राम मंदिर ट्रस्ट का नियंत्रण चंपत राय के हाथों में है और सबसे ज्यादा आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं, तो उन्हें अब तक उनके पद से हटाया क्यों नहीं गया है। यह सवाल उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछा है।

## कच्छ के लिए एक बड़ी उपलब्धि : मुंद्रा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू, मुंबई-अहमदाबाद पहुंचना हुआ आसान

(जीएनएस)।

कच्छ के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, मंगलवार को मुंद्रा के अदाणी एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरूआत हो गई है। अब मुंद्रा सीधे मुंबई और गोवा जैसे शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी।

रीजनल एयरलाइन 'स्टार एयर' के साथ मिलकर शुरू की गई इन उड़ानों से व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मुंबई और गोवा के अलावा, स्टार एयर मुंद्रा को हिंडन, सूरत, बेलगावी, बेंगलुरु, कोल्हापुर और नांदेड़ से भी जोड़ेगी। इस तरह मुंद्रा एयरपोर्ट अब देश के आठ प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा।

इन उड़ानों के शुरू होने से न केवल सफर का समय बचेगा, बल्कि मुंद्रा और उसके आसपास के कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट

और विशाल मल्टी-प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक, इस एयरपोर्ट को एक इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स और बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पोर्ट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब एयर कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलेगी।

मुंद्रा एयरपोर्ट पर 1,900 मीटर लंबा रनवे है, जहां यात्री और कार्गो विमान आसानी से लैंड कर सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों की सुविधा के लिए कई चेक-इन काउंटर, वेटिंग लाउंज, पार्किंग, फूड कोर्ट और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही, यात्रियों के लिए डेडिकेटेड ड्रॉप-ऑफ जोन भी बनाया गया है।

बेहतर कनेक्टिविटी से मुंद्रा पोर्ट और SEZ में काम करने वाली कंपनियों को काफी फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की आवाजाही और कार्गो मूवमेंट आसान हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि इन नए हवाई संपर्कों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में इस क्षेत्र की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। यह विकास अदाणी ग्रुप के एविएशन पोर्टफोलियो के विस्तार का हिस्सा है। ग्रुप फिलहाल मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु और गुवाहाटी जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स का संचालन कर रहा है, जबकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है।

फ्लाइट्स शुरू होने के साथ ही मुंद्रा अब कच्छ के लिए एक प्रमुख एविएशन गेटवे बन गया है। इससे पश्चिमी गुजरात में आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## सदन में दिखा सीएम विजय का फिल्मी अंदाज, थलापति के सिग्नेचर जेस्चर से तिलमिलाई विपक्ष, भड़के उदयनिधि ने क्या कहा?

(जीएनएस)।

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सिनेमा और सियासत का मेल देखने को मिला। अभिनेता से नेता बने और अब राज्य के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में अपने भाषण के अंत में ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विजय ने स्पीकर से अनुमति लेने के बाद अपना मशहूर सिग्नेचर जेस्चर किया।

सीएम विजय का यह वही अंदाज है, जिसे उनके प्रशंसक वर्षों से फिल्मों में देखते आए हैं। जैसे ही यह जेस्टर सामने आया, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। समर्थकों ने इसे एक मजबूत राजनीतिक संदेश बताया, जबकि विपक्ष ने इसे गंभीर बहस की जगह फिल्मी प्रस्तुति करार दिया। इस एक जेस्चर ने विधानसभा की कार्यवाही को राजनीतिक बहस के नए दौर में बदल दिया।

भाषण के बाद वायरल हुआ वीडियो, विजय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। भाषण खत्म करने से पहले उन्होंने अपने फिल्मी करियर से जुड़ा प्रसिद्ध जेस्चर दोहराया। सदन में मौजूद कई सदस्यों ने इस पल को ध्यान से देखा। कुछ ही समय में इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया। समर्थकों ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विजय ने अपनी पहचान और जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा है।

उदयनिधि स्टालिन का तीखा हमला, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विजय के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के अहम मुद्दों पर बात करने के बजाय एक "स्क्रिप्टेड" और "आरोपों से भरी एक्टिंग" पेश की।

उदयनिधि ने कहा कि भाषण में बिजली कटौती, किसानों की परेशानियां, कानून व्यवस्था और चुनावी वादों जैसे विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। उनका दावा था कि जनता जिन सवालों के जवाब चाहती है, उन पर मुख्यमंत्री ने खुलकर बात नहीं की।

विधानसभा की कवरेज पर भी उठाए सवाल, उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा की कार्यवाही के प्रसारण को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि लाइव कैमरों का इस्तेमाल किसी फिल्म की शूटिंग की तरह किया गया, जिससे विजय बिना किसी रुकावट के अपना भाषण पूरा कर सके।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे को हल्के में लिया। विपक्ष के नेता के अनुसार, विजय ने किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों के प्रभाव से जुड़ा बताने की कोशिश की, जो उचित नहीं है। — SUBBU_PSPK

## योगी का राह पर चले शुभेंदु?: 'मुगलों-पठानों के नाम पर नहीं होगी कोई सड़क', बंगाल के मुख्यमंत्री का बड़ा एलान

(जीएनएस)।

कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि कोलकाता में अब मुगलों, पठानों और दमनकारी ब्रिटिश शासकों के नाम पर कोई सड़क या इलाका नहीं रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी। सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर इतिहास को विकृत करने का आरोप लगाया है। आइए, विस्तार से पढ़ते हैं(जीएनएस)।(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नामकरण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शहरों, सड़कों और स्थानों के नाम बदलने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की पहल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को विधानसभा में बड़ा एलान करते हुए कहा कि कोलकाता में अब किसी भी सड़क या इलाके का नाम मुगलों, पठानों या दमनकारी ब्रिटिश शासकों के नाम पर नहीं रखा जाएगा। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब कोलकाता नगर निगम द्वारा सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड किए जाने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार इसे ऐतिहासिक भूल सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य सरकार सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नामों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोग भी इस समिति को सुझाव दे सकेंगे और केवल सच्चे देशभक्तों के नामों पर ही विचार किया जाएगा।

यह पूरा विवाद कोलकाता की प्रमुख सड़क सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड किए जाने के बाद शुरू हुआ। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि यह सड़क पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नाम पर नहीं, बल्कि प्रसिद्ध चिकित्सक और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम कुलपति सर हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखी गई थी। उनका आरोप है कि सरकार ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर रही है।

शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोलकाता की पहचान बंगाली संस्कृति और गौरव से जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिस्टर निवेदिता को छोड़कर किसी विदेशी

# सम्पादकीय

## जनआस्था, जनसहभागिता और राष्ट्रीय चेतना का विराट प्रतीक राममंदिर

राम मंदिर : श्रद्धा, विश्वास और जवाबदेही का प्रश्न, राम भारतीय आत्मा के शाश्वत प्रकाश हैं। कुछ व्यक्तियों की लिप्सा उस प्रकाश को धूमिल नहीं कर सकती, किंतु आस्था के मंदिरों को संदेह और भ्रष्टाचार की छाया से मुक्त रखना आवश्यक है।

क्योंकि जब जनता भगवान को अर्पण करती है, तो वह केवल धन नहीं देती, अपना विश्वास सौंपती है और विश्वास की रक्षा किसी भी सयता, किसी भी व्यवस्था और किसी भी धरमिक संस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है।

भगवान श्रीराम केवल एक धरमिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारतीय चेतना के प्राण हैं। राम भारतीय संस्वृति के आधार हैं, लोकजीवन के आदर्श हैं और सनातन सयता के नैतिक शिखर पुरुष हैं। मर्यादा, त्याग, न्याय, करुणा और सामाजिक समरसता की जो परंपरा भारत को विश्व में विशिष्ट बनाती है, उसके वेंद्र में राम हैं।

भारतीय जनमानस की हर धड़कन में राम बसते हैं। जन्म के समय राम नाम के सोहर (बधाई गीत) से आरंभ होने वाला जीवन, अंतिम यात्रा में भी "राम नाम सत्य है" के उद्घोष के साथ पूर्ण होता है। यही कारण है कि राम केवल मंदिरों में स्थापित देवता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मा के अधिष्ठाता हैं।

पांच सदियों के लंबे संघर्ष, बलिदान और अनगिनत तपस्वी प्रयासों के बाद अयोध्या में रामलला की पुनः प्रतिष्ठा संभव हुई। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मसम्मान और सांस्वृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा और विश्वास को रामलला के श्रीचरणों में सर्मपित किया। किसी ने सोने की चरण पादुका अंपित की, किसी ने गहने, किसी ने अपनी जीवन भर की कमाई। यह दान केवल धन का नहीं था, बल्कि राम के प्रति समर्पण और आस्था का प्रतीक था।

राम मंदिर किसी सरकारी धन से र्निमित आस्था का वेंद्र नहीं है, बल्कि यह जनआस्था, जनसहभागिता और राष्ट्रीय चेतना का विराट प्रतीक है। देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का अंश समिधा की तरह इस निर्माण में सर्मपित किया है।

भारत के कोने-कोने से पत्थर, मिट्टी, जल और पूजनीय सामग्री अयोध्या पहुंचाई गई, वहीं नेपाल से जनकपुर की पूजनीय शिलाएं और धरमिक उपहार आए, थाईलैंड से पवित्र मिट्टी भेजी गई तथा अमेरिका सहित अनेक देशों में बसे रामभक्तों ने आर्थिक सहयोग और श्रद्धा सामग्री सर्मपित की। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि समूचे भारतीय समाज और वैश्विक सनातन चेतना के सांस्वृतिक एकात्म का अद्भुत उदाहरण है। संभवतः अयोध्या का राम मंदिर ऐसा पहला मंदिर है, जिसके निर्माण में राष्ट्र की सामूहिक आस्था, सांस्वृतिक सहभागिता और विश्वव्यापी हिदू चेतना का इतना व्यापक एवं भावनात्मक संगम दिखाई देता है।

ऐसे में यदि मंदिर से जुड़े दान, आभूषण या बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी अथवा अनियमितता की खबरें सामने आती हैं, तो यह सामान्य अपराध नहीं रह जाता। यह करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर आघात है।

यह जनआस्था की चोरी है। मंदिर की संपत्ति पर हाथ डालना वस्तुतः उस विश्वास को चोट पहुंचाना है, जिसने वर्षो तक संघर्ष कर राम मंदिर के स्वप्न को साकार किया।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि इतना विशाल और संसाधन संपन्न ट्रस्ट आखिर इतनी अव्यवस्था का शिकार वैसे हो गया? जहां सुरक्षा के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जहां हर गतिविधि पर निगरानी होनी चाहिए, वहां यदि दान की वस्तुओं और निर्माण कार्यो में अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जवाबदेही का गंभीर संकट है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े संस्थानों में पारर्दशिता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि वहां भी शिथिलता दिखाई दे, तो स्वाभाविक रूप से जनसंदेह जन्म लेता है।

# यूपी शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटी योगी सरकार, प्रदेश में चयन प्रक्रिया हुई शुरू

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा सुधारों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी सक्रिय कदम उठा रहा है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 'अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेज इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन' के लिए प्रदेश में चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

शिक्षा प्रशासन में नवाचार, सुशासन, अधिगम सुधार, प्रभावी प्रबंधन और जनभागीदारी आधारित उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों का चयन कर उनके नाम राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाएंगे. यह पहल उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे शिक्षा सुधारों और नवाचारी प्रशासनिक मॉडलों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

### चयनित होंगे चार बीएसए और छः बीईओ

अपर राज्य परियोजना निदेशक प्रेम रंजन सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश से 4 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) तथा 6 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का चयन किया जाएगा. इसके लिए सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षा प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं. चयन के दौरान नवाचार, बेहतर प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता, अधिगम स्तर

में सुधार, विद्यालयी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश से चयनित अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने कार्यों के माध्यम से प्रदेश में लागू शिक्षा सुधारों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करेंगे.

उल्लेखनीय है कि 'अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेज इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन' भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध राष्ट्रीय स्तर की पहल है. इसका उद्देश्य शिक्षा प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करना तथा देशभर में सफल प्रशासनिक नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणालियों को पहचान दिलाना है.

### यह हैं निर्देश

निर्देशों में कहा गया है कि जनपद ऐसे अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करें, जिन्होंने शिक्षा प्रशासन में नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाकर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हों, विशेष रूप से वे अधिकारी प्राथमिकता में रहेंगे जिनके प्रयासों से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर, विद्यालय प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता या शैक्षणिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला हो.

प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता,जवाबदेही और परिणाम आधारित प्रशासनिक संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए होने वाला यह चयन न केवल उत्कृष्ट अधिकारियों को पहचान दिलाएगा, बल्कि शिक्षा प्रशासन में नवाचार, प्रतिस्पर्धा और बेहतर प्रदर्शन की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते वर्षों में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं. निपुण भारत मिशन, बाल वाटिका, विद्यालय कायाकल्प, स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल शिक्षण संसाधन, मिशन प्रेरणा, शिक्षक प्रशिक्षण और अधिगम गुणवत्ता सुधार जैसे कार्यक्रमों ने विद्यालयी शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है. इन पहलों को सफलतापूर्वक धरातल तक पहुंचाने में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यही कारण है कि अब ऐसे अधिकारियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है.

# भारत की ताकत बढ़ाएगी पीएम मोदी की इंडो-पैसिफिक के तीन देशों की यात्रा- क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करेंगी. भू-राजनीतिक (जियोपॉलिटिकल) कॉम्पिटिशन और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत इस क्षेत्र के प्रमुख समुद्री भागीदारों के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहता है.

दक्षिण-पूर्वी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के ये तीनों देश, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से हैं. इन्हें एक स्वतंत्र, खुले और नियमों से चलने वाले भारत-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत का बेहद जरूरी जोड़ीदार माना जाता है.

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा, पीएम मोदी के इस दौरे का बड़ा मकसद समुद्री सहयोग को बढ़ाना, मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना और क्रिटिकल मिनरल्स तक भारत की पहुंच बनाना है. इसके साथ ही भारत उन देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के हक में हैं.

### इंडोनेशियाः व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आसियान (अरएअठ) गुट का सबसे प्रभावशाली सदस्य है. मलक्का जलडमरूमध्य के पास इसकी खास भौगोलिक स्थिति भारत के समुद्री हितों के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है.

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत और इंडोनेशिया के बीच की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' और गहरी होने की उम्मीद है. साल 2018 में जब से दोनों देशों के रिश्तों को यह बड़ा दर्जा मिला है, तब से दोनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मामलों पर एक-दूसरे के साथ तालमेल काफी बढ़ाया है.

भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के लिए इंडोनेशिया बेहद अहम है और यह दक्षिण-पूर्वी एशिया तक पहुंचने के लिए एक पुल का काम करता है. पीएम मोदी का यह दौरा आसियान (अरएअठ) की केंद्रीय भूमिका के लिए भारत के समर्थन को दिखाएगा. साथ ही यह ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा.

भारत और इंडोनेशिया के करीबी रिश्ते दोनों देशों को अमेरिका और

चीन की बढ़ती दुश्मनी के बीच अपनी स्वतंत्रता (रणनीतिक स्वायत्तता) बनाए रखने में मदद करते हैं.

इंडोनेशिया आसियान (अरएअठ) देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कोयला, पाम ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में व्यापार काफी बढ़ा है.

इंडोनेशिया के पास निकेल और अन्य खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए बेहद जरूरी हैं. इस यात्रा से इस क्षेत्र में सहयोग तेज हो सकता है, क्योंकि भारत अपने ऊर्जा बदलाव (एल्ली१८ ळ१ल्ल२३ङ्गल्ल) और ईवी उद्योग के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन चाहता है. दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा), ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और एलएनजी (छठत्र्) की सप्लाई को लेकर सहयोग बढ़ने की उम्मीद है.

भारत ने मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित सबांग बंदरगाह को विकसित करने में दिलचस्पी दिखाई है. इससे व्यापार तो बेहतर होगा ही, साथ ही पूर्वी हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी भी मजबूत होगी.

इंडोनेशिया भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री भागीदार बनकर उभरा है. दोनों देश समुद्री जहाजों की आवाजाही की जानकारी साझा करने, समुद्री डकैतों को रोकने के अभियानों और खोज व बचाव कार्यों में एक-दूसरे की मदद करते हैं. दोनों देशों के बीच उस समझौते पर बातचीत आखिरी दौर में है, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को अपनी खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात (एक्सपोर्ट) करेगा.

दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंध भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में नियमों पर आधारित व्यवस्था और समुद्री जहाजों की आजादी को बनाए रखने में मदद करते हैं. विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और पूर्वी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह बेहद जरूरी है.

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से पहले, इसी महीने की शुरूआत में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो के साथ '8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक' (खउट) की सह-अध्यक्षता की थी.

7 जून को हुई इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोनों मंत्रियों ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आपसी संबंधों की पूरी समीक्षा की और राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, निवेश, फार्मा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की.

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई चर्चाओं ने आपसी रिश्तों को एक नई रफ्तार दी है, जिसमें जनवरी 2025 में राष्ट्रपति सुबियांतो की भारत की राजकीय यात्रा भी शामिल है. दोनों पक्षों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए और क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों पर आपसी तालमेल व सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

ओडिशा के 'कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज' थिंक टैंक के संस्थापक और अध्यक्ष चिंतामणि महापात्र ने ईटीवी भारत से कहा कि इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा देश है. यह आसियान की चर्चाओं व फैसलों को नेतृत्व देकर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को देखते हुए इंडोनेशिया आसियान का एक ऐसा सही देश है जिससे हमें संपर्क बढ़ाना चाहिए.

भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समझौते को लेकर चिंतामणि महापात्र ने अपनी राय देते हुए कहा कि भारत ने अब आसियान देशों के साथ सुरक्षा और रक्षा से जुड़े रिश्ते विकसित करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि शुरूआत में यह सहयोग केवल आर्थिक स्तर तक ही सीमित था, लेकिन अब यह सुरक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है.

### ऑस्ट्रेलियाः एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना

पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. साल 2020 में दोनों देशों के रिश्तों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया था, जिसने अब एक मजबूत भू-राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक जुड़ाव और आपसी तालमेल को और अधिक मजबूती मिलेगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया 'क्वाड' (दर्४) समूह के जरिए एक-दूसरे के साथ मिलकर बेहद बारीकी से काम करते हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल हैं. इसके अलावा दोनों देश जी20, ईस्ट एशिया समिट, राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) और 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं. यह साझेदारी नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, समुद्री जहाजों की आजादी, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षित व मजबूत सप्लाई चेन बनाने के साझा विचारों को दशार्ती है.

चूंकि दोनों ही देश आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्पों को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन करीबी रिश्तों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है.

दोनों देशों के बीच हुए 'आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते' (एउळअ) के लागू होने से आपसी व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है. प्रधानमंत्री की इस यात्रा से 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते' (उएउअ) को लेकर चल रही बातचीत में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक नियमों में और ढील मिलेगी और बिजनेस करना आसान हो जाएगा.

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट और 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है. ये खनिज भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (एश) अभियान, सेमीकंडक्टर (चिप) निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी हैं.

ऑस्ट्रेलिया में विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों (डायस्पोरा) की सबसे बड़ी आबादी और भारतीय छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या रहती है. इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे को बेहद जरूरी सुरक्षा भागीदार के रूप में देखते हैं. दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग ऑसइंडेक्स (अवरक्ठऊ) नौसैनिक अभ्यास, मालाबार अभ्यास, पिच ब्लैक वायु सेना अभ्यास और टैलिसमैन सेब्रे जैसे युद्धाभ्यासों के जरिए काफी मजबूत हुआ है.

इसके साथ ही, 'परस्पर लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते' से दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की छूट मिलती है, जिससे उनकी मारक और परिचालन क्षमता बढ़ती है.

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी को लेकर कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया की राजधानी) और नई दिल्ली दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं. यह बढ़ता सहयोग समुद्र की निगरानी क्षमता को मजबूत करता है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद करता है.

ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिक अमित दासगुप्ता ने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी अन्य भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है.

पूर्व राजनयिक अमित दासगुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया गए, तो 30 से अधिक वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वह पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा था. इससे पहले राजीव गांधी वहां गए थे. उस दौर से पहले तक, न तो ऑस्ट्रेलियाई लोगों की भारत में कोई खास दिलचस्पी थी और न ही भारतीयों की ऑस्ट्रेलिया में कोई रुचि थी. ऑस्ट्रेलियाई लोग अक्सर मजाक में कहा करते थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल तीन 'C' से जुड़े हुए हैं- क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और करी (भारतीय खाना)."

उन्होंने आगे बताया कि साल 2014 में जब पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, तो उन्होंने तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के सहयोग और समर्थन से इस "नीरस व फीके रिश्ते" को पूरी तरह से एक बेहद महत्वपूर्ण और ठोस साझेदारी में बदल दिया.

दासगुप्ता ने कहा, "साल 2014 के बाद से हमने देखा है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के संबंध एक बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते के रूप में उभरे हैं. चाहे सुरक्षा का मामला हो, रक्षा का क्षेत्र हो या फिर व्यापार समझौता, दोनों देशों के बीच हर स्तर पर मुलाकातें और बातचीत काफी बढ़ी हैं. अब समय आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ इस रिश्ते की अहमियत और ताकत को पूरी तरह से समझे."

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते (ECTA) का जिक्र करते हुए अमित दासगुप्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़कर 52 अरब डॉलर (52 बिलियन डॉलर) हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने ध्यान दिलाया कि ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार 250 अरब डॉलर का है, जो भारत के मुकाबले पांच गुना ज्यादा है.

दासगुप्ता का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस रणनीतिक साझेदारी के जरिए जो बेहतरीन मंच और माहौल तैयार किया है, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बड़े कारोबारियों और नीति निमार्ताओं को अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमारे प्रधानमंत्री की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा को तभी महत्वपूर्ण मानूंगा जब ऑस्ट्रेलियाई पक्ष केवल अच्छे और लुभावने बयान देने से आगे बढ़कर धरातल पर कदम उठाएगा. अब गेंद उनके पाले में है. ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति, सुरक्षा नीति और एशिया के बारे में अपनी पूरी सोच को वॉशिंगटन (अमेरिका) के भरोसे छोड़ रखा था. लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी देशों के सैन्य और रणनीतिक गठबंधन को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलियाई यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है."

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए अमित दासगुप्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़कर 52 अरब डॉलर हो गया है, जबकि इसके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार 250 अरब डॉलर का है, जो कि पांच गुना अधिक है.

दासगुप्ता का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस रणनीतिक साझेदारी के जरिए जो बेहतरीन मंच और माहौल तैयार किया है, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बड़े कारोबारियों और नीति निमार्ताओं को अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा कि वे हमारे प्रधानमंत्री की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा को तभी महत्वपूर्ण मानेंगे जब ऑस्ट्रेलियाई पक्ष केवल अच्छे और लुभावने बयान देने से आगे बढ़कर धरातल पर ठोस जवाब देगा. अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति, सुरक्षा नीति और एशिया के बारे में अपनी पूरी सोच को वॉशिंगटन (अमेरिका) के भरोसे छोड़ रखा था, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है.

# होने वाले पति को खाई में धकेला, फिर इंस्टा पर किया ड्रामा! कौन है कातिल सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी?

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों को तार-तार कर दिया है। जिसे हमसफर मानकर एक शख्स जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने संजो रहा था, उसी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुणे के लोहागढ़ किले पर 26 साल के बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल की 400 फीट गहरी खाई में गिरकर हुई मौत, कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची-समझी खूनी साजिश थी। ये केस इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती-जुलती है।

केतन की हत्या के आरोप में उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और उसके 22 वर्षीय ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिया गोयल और उसके चेतन चौधरी पर केतन के हत्या का आरोप है। पुलिस का कहना है कि केतन को लोहागढ़ किले से करीब 400 फीट गहरी खाई फेंका गया था और बाद में इसे हादसा बताने की कोशिश की गई थी। केतन 18 जून को अपने मंगेतर सिया के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए गया था। बाद में उसका शव खाई से बरामद किया गया।

हैरान करने वाली बात यह है कि मंगेतर केतन को खाई में धक्का देने के कुछ ही घंटों बाद सिया गोयल ने इंस्टाग्राम पर बेहद भावुक पोस्ट लिखकर रोने का नाटक भी किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी।

इस मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले इसके किरदारों को जानना जरूरी है। 26 साल का मृतक केतन विशाल अग्रवाल पुणे जिले के गहुंजे का रहने वाला था। केतन एक बेहद रईस परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने परिवार के बड़े रियल एस्टेट बिजनेस में बतौर डायरेक्टर काम संभाल रहा था। वहीं इस केस की मुख्य आरोपी 20 साल की सिया गोयल पुणे के ही एक बहुत बड़े मसाला कारोबारी की बेटी है।

केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी महीने में हुई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से यह शादी तय हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था और आने वाले नवंबर महीने में राजस्थान के उदयपुर (कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर) के एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस में दोनों की शादी होने वाली थी। यह शादी कितनी भव्य होने वाली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर करीब ₹17 करोड़ खर्च होने वाले थे और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो चार्टर्ड प्लेन तक बुक किए जा चुके थे।

पुलिस के मुताबिक 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए गए थे। कुछ समय बाद वह करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। शुरूआत में इसे हादसा माना गया और सिया ने भी पुलिस को बताया कि तेज हवा के बीच केतन का पैर फिसल गया था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी पूरी तरह बदल गई। सिया गोयल पुणे के एक प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी परिवार से जुड़ी बताई जाती है। परिवार ने उसकी शादी केतन के साथ तय की थी। दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर उत्साहित थे और शादी की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी थीं।

जानकारी के मुताबिक, शादी के लिए राजस्थान के एक शाही पैलेस को चुना गया था। मेहमानों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था तक की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में शादी का बजट करोड़ों रुपये बताया गया है। हालांकि पुलिस जांच में दावा किया गया कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी और किसी अन्य युवक के साथ संबंध में थी। पुलिस के मुताबिक, चेतन चौधरी पुणे के कोंढवा इलाके का रहने वाला 22 वर्षीय युवक है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह पिछले लगभग एक साल से सिया के संपर्क में था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस का आरोप है कि चेतन और सिया केतन को अपने रिश्ते की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इसी वजह से दोनों ने कथित तौर पर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

### केतन शादी को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन सिया को पसंद था चेतन

एक तरफ जहां केतन शादी को लेकर एक्साइटेड था और अपनी होने वाली पत्नी सिया से बहुत प्यार करता था, वहीं सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया गोयल पिछले करीब एक साल से पुणे के कोंढवा के रहने वाले 22 साल के चेतन चौधरी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी।

सिया इस अरेंज मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह चेतन से प्यार करती थी और उसे लगता था कि केतन अग्रवाल उन दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसने देखा कि शादी की तारीख नजदीक आ रही है और परिवार के दबाव में शादी को टालना नामुमकिन है, तो उसने और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को हमेशा-हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का एक खौफनाक और जानलेवा प्लान तैयार कर लिया। केतन अपनी मंगेतर को खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। शादी से पहले दोनों ने इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर घूमने जाने का प्लान बनाया था। इसके लिए केतन ने सारी बुकिंग और टिकट्स भी फाइनल कर दिए थे। लेकिन सिया इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी। उसने केतन से झूठ बोला कि उसका पासपोर्ट कहीं खो गया है, जिसके चलते वह ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। बाद में पुलिस जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि सिया ने खुद ही अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया था ताकि उसे केतन के साथ बाहर न जाना पड़े।

यही नहीं, सिया का जन्मदिन आने वाला था और केतन उसके प्री-बर्थडे को बेहद यादगार बनाना चाहता था। इसके लिए केतन ने महाबलेश्वर के एक बेहद महंगे और लग्जरी रिसॉर्ट में पूरे 40 कमरे बुक कर दिए थे, जहां एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। इसी बीच, सिया ने ही केतन के सामने लोहागढ़ किले पर जाकर प्री-वेडिंग फोटोशूट और प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने ट्रैकिंग करने का आइडिया रखा, जिसे केतन खुशी-खुशी मान गया। उसे क्या पता था कि यह ट्रैकिंग उसके जीवन का आखिरी सफर बनने वाली है।

पुलिस के मुताबिक केतन को मारने की साजिश एक दिन में नहीं रची गई थी। सिया और चेतन ने इसके लिए बकायदा रेकी की थी। सबसे पहले 31 मई को दोनों लोहागढ़ किले पर गए थे, जहां उन्होंने इस पूरी वारदात का खाका तैयार किया कि किस जगह से धक्का देने पर मौत पक्की है।

इसके बाद 14 जून को सिया और केतन दोबारा लोहागढ़ किले पर पहुंचे। इस दौरान सिया के साथ उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी वहां छिपा हुआ था। प्लानिंग के मुताबिक, केतन को सांप का डर दिखाकर असंतुलित करने और खाई में धकेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दिन किस्मत अच्छी होने के कारण केतन बच गया और उसे सिया पर कोई शक भी नहीं हुआ।

इसके ठीक पांच दिन बाद यानी 18 जून की सुबह सिया दोबारा केतन को अपने जाल में फंसाकर लोहागढ़ किले के ऊपर ले गई। सुबह करीब 10:30 बजे जब वे किले के एक सुनसान और खतरनाक पॉइंट पर पहुंचे, तो पीछे से चेतन चौधरी भी वहां आ गया।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

# 'राम के घर चोरी, अरे! राम राम राम', अयोध्या मंदिर मामले पर शेखर सुमन ने कसा तंज, बोले- ट्रस्ट तो टूटा है

**राम मंदिर में चोरी के मामले पर शेखर सुमन ने अपने शो 'शेखर टुनाइट' में तंज कसते हुए कहा कि "कलयुग ओवरटाइम काम कर रहा है।" इससे पहले भी वह अपने राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य वाले बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं।**

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, शेखर सुमन इस वक्त अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' को लेकर काफी चर्चा में हैं। हर एपिसोड की शुरूआत में वो अपने अंदाज में देश-दुनिया में चल रहे मुद्दों पर कुछ पंक्तियां जरूर कहते हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में तंज कसते हुए कहा है कि कलयुग ओवरटाइम काम कर रहा है।

शेखर सुमन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'मंदिर में भी चोरी? कलयुग ओवरटाइम काम कर रहा है।' इसी के साथ वीडियो में वो कह रहे हैं, 'अयोध्या से राम मंदिर में चोरी होने की खबर आई। राम के घर चोरी? अरे! राम राम राम। इस बारे में जब हमने भाजपा वालों से पूछा तो एक भाजपाई ने झुंझला के कहा अरे भाई साहब, अयोध्या से हमारी सीट चोरी हो गई है, तुम्हें चढ़ावे की पड़ी है।'

शेखर सुमन ने आगे कहा, 'जब मीडिया ने सरकार के किसी मंत्री से इस चोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का मामला है। सही कहा मंत्री जी मामला 'ट्रस्ट' का ही है। और वो इतनी बार टूट चुका है कि अब ट्रस्ट पर ट्रस्ट ही नहीं रहा रे।'

कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर आप को किया था रोस्ट

इससे पहले शेखर सुमन ने कॉकरोच जनता पार्टी और पीएम मोदी का भी अपने वीडियो में जिक्र किया था। शेखर ने कहा था, 'मेरे प्रिय कॉकरोचों, उम्मीदें तो आपने जगा दी हैं, अब आपसे बस इतना आग्रह है, निवेदन है जंतर मंतर से छू मंतर मत हो जाइएगा। मतलब, पलट मत जाइएगा क्योंकि जंतर मंतर का पलटने का पुराना इतिहास है। देखिए ना केजरीवाल जी यहां से कह के गए कि राजनीति में नहीं जाऊंगा, फिर पलट गए। बोले सरकारी मकान नहीं लूंगा, नहीं नहीं नहीं फिर पलट गए। बोले सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर पलट गए।'

उन्होंने आगे कहा था, 'लेकिन कॉकरोचों आप मत पलटिएगा क्योंकि कॉकरोच अगर एक बार पलट गया, तो फिर सीधा नहीं हो सकता, जब तक किया ना जाए। बस एक सलाह है हमारी कि जिंदा लोकतंत्र में आवाज जिंदा रहनी चाहिए। मानना है तो मानिए, वरना औंधे पड़े-पड़े हाथ-पैर मारते रहेंगे. फिर AAP का झाड़ू भी कुछ नहीं कर पाएगा।'

शेखर सुमन ने स्क्रीन स्पॉटलाइट पर अपने छोटे से राजनीतिक करियर के बारे में खुलकर बात की है। शेखर से पूछा गया कि 'शेखर टूनाइट' के पहले एपिसोड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य होने की वजह से उन्हें शो में लाना आसान हुआ? इसका जवाब उन्होंने एक लाइन में देते हुए कहा कि नहीं, मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए बीजेपी का सदस्य था।

शेखर के जवाब के बाद उनसे सवाल किया गया कि तो फिर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला क्यों किया? इस पर अभिनेता ने कहा, 'पता नहीं। कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप मुश्किल में फंस जाते हैं। कुछ वजहें आपके बस में नहीं होतीं। मेरे साथ ऐसा दो बार हुआ है कि मैंने वो काम किया जो मैं नहीं करना चाहता था।

# काकादेव में केडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बड़े कोचिंग संस्थान सहित 31 सील, बेसमेंट में चल रही थी क्लास

(जीएनएस)।

कानपुर। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में बेसमेंट में चल रही कोचिंग क्लासेज में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। केडीए (कानपुर डेवलपमेंट अथारिटी) ने 31 कोचिंग क्लासेज में छापा मारा। कई बड़े संस्थानों में बेसमेंट में क्लास चलने की वजह से तत्काल छुट्टी करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया।

**फिजिक्स वाला, विद्यापीठ और वर्कस्पेस में पहुंची टीम**

लखनऊ में अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद सीएम की सख्ती को देखते हुए सोमवार रात केडीए की टीम ने काकादेव में छापेमारी शुरू कर दी। शाम को निकले विभाग के दस्ते ने तीन घंटे के भीतर ही फिजिक्स वाला, विद्यापीठ और वर्कस्पेस समेत 16 कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील कर दिए। इसके साथ ही 22 प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर नोटिस दी जा रही है।

**बेसमेंट में चल रही थी क्लास**

उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के आदेश पर केडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार शाम को कोचिंग मंडी में जांच शुरू की। काकादेव में विद्यापीठ, फिजिक्स वाला, संजीव राठौर कोचिंग, वर्क स्पेस समेत 16 कोचिंग में से कई बेसमेंट में चलते मिले जबकि कुछ में निकास के लिए नक्शे के अनुरूप व्यवस्था नहीं की गई थी।

**नक्शे की अनदेखी, 22 प्रतिष्ठान चिन्हित**

नक्शे की अनदेखी पर जोन एक के दस्ते ने तीन, जोन दो बी के दस्ते ने पांच, जोन तीन के दस्ते ने तीन और जोन पांच के दस्ते ने पांच प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। इसके साथ ही 22 अन्य प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित किया है। इनके नक्शे की जांच के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

**कोचिंग संचालकों संग पुलिस आयुक्त करेंगे बैठक**

लखनऊ में हुई घटना के बाद शहर की कोचिंग मंडी को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ है। पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी प्रमुख कोचिंग संचालकों के साथ ही अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोचिंग संचालकों को संस्थानों में अग्निसुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अग्निशमन विभाग कोचिंग संस्थानों में अग्निसुरक्षा मानकों की पड़ताल करेगा और माकड्रिल कर संचालकों व छात्र-छात्राओं को जागरूक करेगा।

**मंगलवार को 16 कोचिंग संस्थान व प्रतिष्ठान सील**

मंगलवार को भी प्राधिकरण की टीम ने बिना मानक की बनी और बेसमेंट में चल रही व्यावासायिक गतिविधियों को लेकर 16 कोचिंग संस्थान और प्रतिष्ठान सील किए थे।

# विहिप की शीर्ष बैठकों तक पहुंची रामलला मंदिर चढ़ावा चोरी की आंच, अयोध्या में होने वाली 5 दिवसीय मीटिंग स्थगित

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। अयोध्या में रामलला मंदिर के दानपात्रों से करोड़ों की चढ़ावा चोरी की आंच अब विहिप की शीर्ष बैठकों तक पहुंच गई है। राम के आंगन अयोध्या में ही एक दिनों बाद से शुरू होने वाली पूर्व निर्धारित यह बैठकें अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दी गई है।

विहिप की केन्द्रीय प्रबंध समिति व प्रन्यासी मंडल की नीति निर्धारक बैठकें 25 से 29 जून तक आयोजित थी, जिसमें दान चोरी प्रकरण पर भी विस्तार से चर्चा भी तय थी, जिसमें हंगामा भी संभावित था।

संगठन के शीर्ष सूत्रों के बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आगे यह बैठक कब और कहां होगी, यह जल्द तय किया जाएगा।

इसके पूर्व विहिप की मार्गदर्शक मंडल व उच्चाधिकार समिति की बैठक 18 व 19 जून को हरिद्वार में हुई थी, जिसमें भी यह मुद्दा छाया रहा था। उस बैठक में देशभर के प्रमुख संत मौजूद थे। जिसमें मांग उठी कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रामजी के एक-एक पैसे का जिम्मेदार बताते हुए ट्रस्ट के साथ ही रामालय ट्रस्ट और राम जन्म मंदिर पुनर्निर्माण ट्रस्ट के भी खातों की जांच की जाए।

स्थगित हुई केंद्रीय प्रन्यासी मंडल और केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठकों में विश्व भर से 300 से अधिक विशिष्ट पदाधिकारी आमंत्रित थे।

वर्ष में दो बार होने वाली यह बैठक नीति निर्धारक हैं, जिसमें अगले छह माह के अभियान, मुद्दे और कामकाज तय किए जाते हैं। जिसकी पिछली बैठकें हरियाणा के हस्तिनापुर में हुई थी।

विहिप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, बैठक में पूरे प्रकरण पर चर्चा के साथ विमर्श तय था कि कैसे दानपात्र मामले में खामियों को दूर कर व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया जाए, पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही संगठन में विमर्श कर बैठक की तिथि तथा स्थान तय किया जाएगा।

# लखनऊ अग्निकांड के बाद खुला एलडीए में भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा

(जीएनएस)।

लखनऊ। अग्निकांड की जांच की आंच मंगलवार को एलडीए के भीतर पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनवरी से 20 जून तक अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांग लिया। रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों के चेहरे पर सिकन और एसी कमरे में बैठकर भी माथे पर पसीना साफ दिखा।

कभी इस कमरे भागकर एक फाइल उठाते तो कभी दूसरे कमरे से कुछ और रिकार्ड। आखिर जब रिपोर्ट तैयार हुई तो एलडीए में पिछले कई वर्षों से व्याप्त भ्रष्ट तंत्र का चेहरा सामने आ गया। पता चला कि एलडीए अफसरों की मिलीभगत से ही अवैध अपार्टमेंट, होटल और व्यावसायिक भवन बन गए।

अलीगंज की तरह ही गोमतीनगर, आशियाना, कानपुर रोड सहित शहर के 1043 आवासीय भूखंडों और भवनों पर अवैध रूप से व्यावसायिक कांप्लेक्स और भवन बनाए गए हैं। इसमें कुछ का एकल आवासीय यूनिट का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। नई भवन निर्माण नीति के तहत इनको शमन के लिए नोटिसें भी भेजी गई हैं।

हालांकि, केवल 257 लोगों ने ही अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक निर्माण का शमन कराने के लिए एलडीए से संपर्क किया है। इसी तरह चारबाग में आवासीय भू उपयोग के विपरीत चल रहे 157 होटल बिना नक्शे पास हुए तैयार किए गए हैं। होटल लेवाना अग्निकांड के बाद इन होटलों पर भी एलडीए ने नोटिस भेजकर खानापूर्ति की है।

**दो हजार ध्वस्तीकरण आदेश**

एलडीए के विहित न्यायालय में अलीगंज के कांप्लेक्स की तरह ही करीब दो हजार बड़े निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं। इसमें सबसे अधिक आदेश गोमतीनगर और चौक से जुड़े क्षेत्रों के हैं। इन ध्वस्तीकरण आदेश के बाद भी एलडीए का बुलडोजर नहीं चल सका है।

**अफसरों को बांटे फ्लैट**

एलडीए अफसरों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ का मामला नजूल की भूमि पर बने यजदान अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण के समय सामने आया था। प्राग नारायण रोड, वजीर हसन रोड और डालीबाग में यजदान बिल्डर की आठ संपत्तियों का पता चला था। इसे एकल यूनिट का नक्शा दाखिल करके बनाया गया था। एक के बाद एक कई नक्शों के निरस्त होने के बावजूद अवैध निर्माण होते गए।

बिल्डर ने वर्ष 2011 और 2012 में एलडीए के कई इंजीनियरों और अफसरों को अपने अपार्टमेंट में फ्लैट गिफ्ट किए थे। पुराना किला के पास लखनऊ मांटेसरी स्कूल के ठीक बगल में यजदान बिल्डर ने एकल यूनिट का नक्शा 27 मार्च 2015 को जमा किया और यह 25 जून 2015 को निरस्त हो गया। इसके बावजूद एक बड़ा अपार्टमेंट खड़ा हो गया। एकल आवासीय यूनिट का नक्शा पास कराकर महानगर सहित कई इलाकों में 200 से अधिक अपार्टमेंट बन गए है।

# सपा सांसद राजीव राय ने करोड़ों की प्रभु राम की मूर्ति चोरी के आरोप लगाए, अयोध्या के युवक ने बता दिया सच

**सपा सांसद राजीव राय ने दान की गई प्रभु राम की करोड़ों की मूर्ति चोरी होने के बात कही। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से इसके बारे में जानकारी देने को कहा है। इस पर अयोध्या के युवक ने उनको सच बता दिया। राजीव राय ने उठाए गंभीर सवाल**

मऊः उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट से सपा सांसद राजीव राय ने राम मंदिर चंदा चोरी पर एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र ने करोड़ों रुपये की भगवान राम की एक मूर्ति राम मंदिर ट्रस्ट को दी थी। कहा कि इसको पता करा लें कि यह मूर्ति बची है या फिर ये भी चोरी हो गई है।

घोसी लोकसभा सीट से सपा सांसद राजीव राय ने एक्स हैंडल पर फोटो और वीडियो के साथ एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए ये तंजौर शैली की भगवान की करोड़ों रुपये की मूर्ति बेंगलुरु के मेरे मित्र जय फनीश ने दान किया था। जिसे शुरू में ट्रस्ट मैनेजमेंट ने म्यूजियम में रखने के लिए कहा, जिसकी वजह से भक्त ने देने से मना कर दिया था और कहा कि इससे इच्छा हम अखिलेश यादव जी द्वारा बनवाए जा रहे केदारेश्वर मंदिर में स्थापित कराएंगे। इतना सुनते ही राम मंदिर न्यास ने मंदिर में स्थापित करना स्वीकार कर लिया।

आगे राजीव राय ने कहा कि कृपया श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्पष्ट करें कि ये मूर्ति बची है या चोरी हो गई? वहीं, राजीव राय के पोस्ट पर एक मोहित यादव नाम के यूजर ने लिखा है कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। ये मूर्ति बची है, क्योंकि ये मंदिर परिसर के बाहर स्थापित है। एक अन्य यूजर विकास शुक्ला ने लिखा है कि फालतू की बात कर रहे हो आप लोग। केवल गुप्त दान की रसीद नहीं मिलती है। बाकी इन सबकी प्रॉपर रसीद दी गई है। एक मनीष सिंह यूजर ने लिखा है कि निश्चित तौर पर मूर्ति गुजरात प्रस्थान कर चुकी होगी। अन्य यूजर भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

# लखनऊ में फिर आग का कहरः इरम कॉलेज के ऑफिस में लगी आग, फर्नीचर-फाइलें जलीं; बड़ा हादसा टला

(जीएनएस)।

लखनऊ के इरम कॉलेज के कार्यालय में मंगलवार दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

**कैंपल रोड स्थित इरम स्कूल में लगी आग**

लखनऊः राजधानी लखनऊ में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित शेखपुर हबीबपुर में मंगलवार दोपहर इरम कॉलेज के कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चौक फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

**दोपहर में मिली आग लगने की सूचना**

फायर विभाग के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3:50 बजे कंट्रोल रूम को इरम कॉलेज के कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही चौक फायर स्टेशन से दो मिनी फायर टेंडर (एमएफई) और फायरकर्मियों की टीम मौके के लिए रवाना की गई।

**ऑफिस का फर्नीचर और दस्तावेज आग की चपेट में आए**

मौके पर पहुंचने पर दमकल कर्मियों ने पाया कि कॉलेज के कार्यालय में रखा फर्नीचर, महत्वपूर्ण फाइलें और आलमारियां आग की चपेट में आ गई थीं। फायर टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए पंपिंग शुरू की और कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया।

**शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका**

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम भी मामले की जांच करेगी।

# कैसे लीक हुआ राम मंदिर चढ़ावे में गबन का सीक्रेट? मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले 'भेदिया' की हो गई पहचान

(जीएनएस)।

अयोध्या। राम मंदिर की दानराशि में गबन प्रकरण की जानकारी मीडिया तक पहुंचाने वाले 'भेदिया' को खोज लिया गया। अब इस समूह पर कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि, अभी संघ के बड़े पदाधिकारियों की सहमति की प्रतीक्षा है।

यह समूह रामजन्मभूमि परिसर के सेवादारों व ट्रस्ट कर्मियों से जुड़ा है। इसने न केवल मंदिर व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव टिन्नू के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि यह बात मीडिया तक भी पहुंचाई।

**टिन्नू का दबदबा नागवार गुजरा**

पखवारे भर की उठापटक व एसआईटी जांच के बीच ही सूचना लीक करने वाले को खोज कर इसकी जानकारी संघ के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। उन ट्रस्ट पदाधिकारी को भी जानकारी दे दी गई है, जिनका टिन्नू करीबी है। इस प्रकरण के तार परिसर में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ से जुड़े हैं, अन्यथा इसे अंदर ही अंदर दबाने की तैयारी थी।

दानराशि में गबन मामले की अब तक की जांच में स्पष्ट है कि यह खेल वर्षों से चल रहा था। रामजन्मभूमि परिसर से यह बाहर भी नहीं आ पाता, यदि वहीं के लोग इसे मीडिया तक न लाते। सूत्रों का कहना है कि मंदिर व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव टिन्नू का दबदबा परिसर के ही एक समूह को नागवार गुजर रहा था।

**मामला दबता देख मीडिया में किया लीक**

टिन्नू ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही परिसर की व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। उसका हर कार्य में प्रभावी दखल रहता था। वह करीबी तो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी का था, परंतु उसकी अन्य दोनों जिम्मेदारों के समर्थकों से भी पटती थी।

प्रशासन का वाकी-टाकी उसके पास रहने से वह बड़े जनसमूह को विशिष्ट दर्शन भी करा देता था। इन्हीं कारणों से उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने का चक्रव्यूह रचा गया। पहले उससे नजदीकियां बढ़ाई गईं और सारे राज इकट्ठा किए गए। फिर उन्हीं पदाधिकारी को सूचना दी गई, जिनका वह विश्वस्त रहा।

बाद में मामला दबते देख मीडिया में जानकारी लीक कर दी गई। इस घटनाक्रम का सूत्रधार कौन बना, इसे कई दिनों से खोजा जा रहा था। अब उन्हें तलाश लिया गया और संघ के पदाधिकारी व मंदिर व्यवस्था के जिम्मेदारों तक यह जानकारी पहुंचा भी दी गयी है।

जल्द ही इस समूह के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी है। अभी इस प्रकरण के पटाक्षेप की प्रतीक्षा है। इस समूह में ट्रस्ट कर्मियों के साथ कुछ स्वयंसेवक भी हैं।

**अयोध्या के नहीं हैं 'भेदिया'**

सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों ने सूचना फैलाई, वे स्थानीय नहीं हैं। संघ व विहिप से तो जुड़े हैं, परंतु अन्य जिलों से यहां आकर सेवारत हैं। ये भी संघ के बड़े पदाधिकारी के विश्वस्त हैं, इसलिए तुरंत कार्रवाई से बचा जा रहा है।

उधर, एसआईटी जांच के कारण परिसर के कर्मियों में इतना भय व्याप्त हो गया है कि अब वे अपने परिचितों से भी मोबाइल फोन पर बात करने से घबरा रहे हैं। कुछ लोगों के मोबाइल जमा करा लिए जाने की भी सूचना मिली है।

# लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर को मिली रफ्तार, 384 करोड़ रुपये में बनेंगे 5 एलीवेटेड स्टेशन, इस कंपनी को मिला टेंडर

**यूपीएमआरसी ने ठाकुरगंज से वसंतकुंज सेक्शन के निर्माण का ₹384 करोड़ का ठेका रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को दिया है.**

(जीएनएस)।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. चारबाग से वसंतकुंज के बीच प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (लखनऊ मेट्रो फेज-1बी) के तहत एलिवेटेड सेक्शन के लिए लगभग 384 करोड़ रुपये (लगभग 453 करोड़ रुपये ऋळ सहित) का प्रमुख सिविल निर्माण टेंडर आवंटित किया गया है. यह टेंडर मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को ठाकुरगंज मेट्रो स्टेशन से वसंतकुंज मेट्रो स्टेशन के बीच एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर और पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिया गया है.

मेट्रो रेल कारपोरेशन के जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह टेंडर यूपीएमआरसी की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए दिया गया है. विस्तृत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को सफल बिडर चुना गया और इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई.

यह परियोजना लखनऊ में शहरी परिवहन को मजबूत करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, सड़क पर जाम कम लगेगा और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. इस टेंडर के तहत मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड लगभग 4.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण करेगी, जिसमें स्टेशन के हिस्से भी शामिल हैं. इसके साथ ही मुख्य लाइन को डिपो के प्रवेश और निकास से जोड़ने के लिए 740 मीटर लंबा रैंप भी बनाया जाएगा.

**ये पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन शामिल**

ठाकुरगंज मेट्रो स्टेशन, बालागंज मेट्रो स्टेशन, सरफराजगंज मेट्रो स्टेशन, मूसाबाग मेट्रो स्टेशन, वसंतकुंज मेट्रो स्टेशन

इस कार्य में सहायक संरचनाएं, प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (ढएइ), वास्तु कार्य, जल आपूर्ति प्रणाली, स्वच्छता व्यवस्था, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहरी विकास कार्य, अग्निशमन प्रणाली और विद्युत एवं यांत्रिक (E&M) कार्य भी शामिल हैं. कार्य शुरू होने की तिथि से 24 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा. लखनऊ मेट्रो फेज-1बी, यूपीएमआरसी की उस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत शहर में सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ मास रैपिड ट्रांजिट सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.

यह कॉरिडोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा और यात्रियों को सड़क परिवहन की तुलना में तेज और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराएगा. यह नया मेट्रो सेक्शन आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक क्षेत्रों और परिवहन केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे नागरिकों की दैनिक यात्रा अधिक आसान होगी. निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी.

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि इस टेंडर का दिया जाना लखनऊ मेट्रो फेज-1बी के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह कॉरिडोर नागरिकों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा. यूपीएमआरसी समय पर, गुणवत्ता के साथ और विश्वस्तरीय मानकों पर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. वसंतकुंज मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है. इसके अलावा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के भूमिगत सेक्शन के निर्माण के लिए भी शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा.

# राम मंदिर के ध्वजारोहण में नहीं शामिल होंगे दोनों डिप्टी सीएम, लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के चलते दौरा रद्द

(जीएनएस)।

अयोध्या, रामनगरी अयोध्या में मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के होने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोचिंग में हुई अग्निकांड की घटना की वजह से दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोजित होगा। कमलेश

श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में हुई जनहानि के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर 23 जून के सभी संगठनात्मक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के प्रस्तावित कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए गए हैं।

महानगर अध्यक्ष ने कहा कि इस दुखद घटना के कारण पार्टी कार्यकताओं से भी सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर में आयोजित होने वाला ध्वजारोहण कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगा। भाजपा पदाधिकारियों ने हादसे में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

# लखनऊ में आग लगी, खान सर के कोचिंग में पहुंच गई इंस्पेक्शन टीम

**लखनऊ अग्निकांड के बाद देशभर में फायर सेफ्टी को लेकर जांच अभियान तेज हो गया है. इसी क्रम में बिहार फायर डिपार्टमेंट की टीम पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर में निरीक्षण के लिए पहुंची. टीम ने संस्थान में फायर सेफ्टी के इंतजाम, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों की जांच की.**

पटना, लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे देश में फायर सेफ्टी को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है. इसी क्रम में बिहार फायर डिपार्टमेंट की टीम पटना स्थित खान सर के ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में निरीक्षण के लिए पहुंची. टीम ने कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी के इंतजाम, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), अग्निशमन उपकरण, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया. अधिकारियों ने यह भी जांचा कि किसी आपात स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं.

बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार है, जब फायर विभाग की टीम खान सर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची है. इसके पहले भी 7 जून को खान सर (फैजल खान) कोचिंग में इंस्पेक्शन हुआ था. तब कई कमियां मिलीं(जीएनएस)।. जैसे स्प्रिंकलर और डिटेक्टर सही नहीं, पंप हाउस नहीं थे.

**इंस्पेक्शन में क्या मिला?**

विभाग ने सात से दस दिन में सुधार का नोटिस दिया था. सोमवार को दूसरी जांच के बाद अब अग्निशमन पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने कहा कि काम में प्रगति है लेकिन उस तरीके की प्रगति नहीं है जो होनी चाहिए. फायर स्टेयर बनाने का काम पूरा नहीं हुआ. स्प्रिंकलर और डिटेक्टर अभी भी ऑटोमैटिक नहीं हैं. पंप हाउस एक लगा है, पर इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा. विभाग ने फिर दस दिन का समय दिया है और कहा है कि अगर मानक पूरे नहीं हुए तो नियमानुसार कार्रवाई होगी. डीआईजी मनोज कुमार नट पहले ही कह चुके हैं कि मानक पूरे न होने पर संस्थान बंद करने की कार्रवाई होगी. इसलिए काम शुरू हुआ है और कुछ प्रगति है पर बड़े काम अभी बाकी हैं और विभाग संतुष्ट नहीं है.

# लखनऊ अग्निकांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला; पूरे परिसर का होगा फायर ऑडिट, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

**कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.**

(जीएनएस)।

लखनऊ : राजधानी में हाल ही में एक कोचिंग संस्थान में हुई आगजनी की दुखद घटना के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर का व्यापक फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समग्र समीक्षा कर भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना है.

कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण विश्वविद्यालय प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि लखनऊ की हालिया घटना हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है. फायर ऑडिट के माध्यम से सभी शैक्षणिक विभागों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों

और पुस्तकालयों में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की तकनीकी समीक्षा कराई जाएगी.

सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, फायर ऑडिट की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाएगी. रिपोर्ट में दिए गए सुझावों और निदेर्शो के अनुरूप परिसर में आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्काल उठाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा मानकों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिसर में अग्नि सुरक्षा और छात्र हितों को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही थी. इस क्रम में अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) की ओर से 13 जून को विश्वविद्यालय के सभी विभागों और संकायों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया था. पत्र के माध्यम से विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों (फायर एक्सटिंग्विशर) की संख्या, उनकी कार्यशीलता तथा वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा अभियान का दायरा मुख्य परिसर तक सीमित न रखते हुए संबद्ध महाविद्यालयों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. सभी संबद्ध कॉलेजों को अपने-अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से विस्तृत दिशा-निदेर्शो सहित आधिकारिक पत्र जारी किया जा रहा है, ताकि विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

# जापान की पहली महिला पीएम का पहला भारत दौरा, गुवाहाटी में क्यों टली मोदी से मुलाकात?

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आ सकती हैं. मंगलवार सुबह सूत्रों ने बताया कि "लॉजिस्टिक्स (प्रबंधन और व्यवस्था) से जुड़ी दिक्कतों" के कारण उनकी यह यात्रा नई दिल्ली में ही आयोजित होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के लिए दिल्ली के अलावा गुवाहाटी के नाम पर भी विचार किया गया था.

सूत्रों ने कहा, "प्रधानमंत्री ताकाइची की अपने देश की व्यस्तताओं को देखते हुए, भारत आने और यहां से वापस लौटने के बीच का समय बहुत कम है. इसे ध्यान में रखते हुए और राजधानी से बाहर की यात्रा से जुड़ी अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स की समस्याओं के कारण, यह दौरा अब दिल्ली में ही होने की उम्मीद है."

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कार्यक्रम होने से दोनों पक्षों को उन खास योजनाओं और मुलाकातों को शामिल करने का मौका मिलेगा, जो भारत-जापान के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं.

पिछले हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि जापानी प्रधानमंत्री के 1 जुलाई को गुवाहाटी आने की संभावना है, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन करेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व अन्य फ्रांस के एवियन में ऋ७ समिट 2026 के दौरान फोटो के लिए पोज देते हुए.

मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "इस बात की संभावना है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गुवाहाटी में शिखर स्तर की बैठक करने के लिए 1 जुलाई को गुवाहाटी का दौरा करें."

जापान के स्थानीय मीडिया ने भी हाल ही में खबर दी थी कि ताकाइची जुलाई की शुरूआत में असम का दौरा करने वाली हैं. जापानी अखबार 'निक्केई' की 18 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरे पर उनके साथ 50 से अधिक जापानी कंपनियों और संगठनों के बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे.

इस बीच, जापानी मीडिया 'एनएचके' (NHK) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के ठोस कदमों पर चर्चा होने की उम्मीद है. यह चर्चा पिछले साल पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान घोषित अगले दशक के 'भारत-जापान संयुक्त विजन' पर आधारित होगी.

इसी महीने की शुरूआत में फ्रांस में हुए 'जी7 शिखर सम्मेलन' (ऋ७ र४३) के दौरान पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची से मुलाकात की थी. उस दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत और जापान व्यापार और निवेश को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को गहरा करना जारी रखेंगे.

जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाने वाली सनाए ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं. संयोग की बात है कि दिसंबर 2019 में शिंजो आबे भी पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए गुवाहाटी आने वाले थे, लेकिन तब उनका वह दौरा स्थगित करना पड़ा था.

# लखनऊ अग्निकांडः आमने-सामने आए ब्रजेश पाठक और अखिलेश, डिप्टी सीएम बोले- निर्माण सपा सरकार में हुआ

(जीएनएस)।

लखनऊ, अलीगंज अग्निकांड पर विपक्ष द्वारा राजनीति किए जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा है कि यह हादसा आपकी सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। उन्होंने कहा कि इस हृदयविदारक घटना में 15 लोगों की जान गई है और आप एसी कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं।

ब्रजेश पाठक ने अलीगंज अग्निकांड को अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना बताते हुए कहा कि प्लॉट आवंटन से लेकर इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण का कार्य आपकी ही सरकार के दौरान हुआ था। आपने इसे सील करके सील खोलने का काम किया था। ध्वस्तीकरण के आदेश को रद करने का काम किया था। ये दर्दनाक घटना आप के ही सरकार के कुकृत्यों का यह नतीजा है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सारे कार्यक्रम रद करके स्वयं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। चार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जितने भी लोग इस घटना में जवाबदेह पाए जाएंगे सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके दर्द को समझते हुए सरकार हर संभव मदद और न्याय सुनिश्चित करेगी।

**अखिलेश सरकार में कैसे मिली भवन निर्माण की इजाजत?**

अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार वाले इकोसिस्टम ने पूरे प्रदेश में ऐसी खतरनाक इमारतों को बनाने का रास्ता खोल दिया, जो आज लोगों की जान ले रही हैं। ये भवन 1980 में लॉटरी से आवंटित तो हुआ था, लेकिन असली खेल अखिलेश यादव के राज में हुआ।

20 अगस्त 2014 को अखिलेश सरकार ने 1992 वर्गफुट का आवासीय नक्शा पास कर दिया। 2016 में अवैध निर्माण का मुकदमा दर्ज हुआ, 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश भी आ गया। लेकिन मात्र 2 महीने बाद, 5 जुलाई 2016 को अखिलेश सरकार ने ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द कर दिया। आखिर क्यों और किसके दबाव में?

सैटेलाइट तस्वीरें भी सब कुछ बेनकाब करती हैं। दिसंबर 2015 में प्लॉट बिल्कुल खाली था, मगर फरवरी 2016 में निर्माण शुरू हुआ और जून 2016 तक इमारत बनकर तैयार हो गई। यानी नियम-कानून को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से नक्शा पास कराया गया, निर्माण कराया गया और सब अखिलेश सरकार की नाक के नीचे चलता रहा। क्या अखिलेश के समय किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? क्या कोई जवाबदेही तय हुई? बिल्कुल नहीं!

# लखनऊ अग्निकांड का असरः गाजियाबाद में जीडीए का बड़ा एक्शन, कोचिंग सेंटर, प्ले स्कूल और लाइब्रेरी सील

(जीएनएस)।

गाजियाबादः लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में सोमवार को लगी भीषण आग में 15 छात्रों की मौत के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) हरकत में आ गया है। हादसे के अगले ही दिन प्राधिकरण ने शहरभर में बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान शुरू कर दिया। मंगलवार को प्रवर्तन टीमों ने कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई करते हुए मानकों की अनदेखी कर रहे कोचिंग सेंटर, प्ले स्कूल, लाइब्रेरी समेत कई प्रतिष्ठानों पर ताले जड़ दिए।

**लखनऊ हादसे के बाद तेज हुआ अभियान**

दरअसल, कुछ समय पहले इंदिरापुरम के गौर ग्रीन एवेन्यू में आग लगने के बाद भी जीडीए ने अभियान चलाया था। उस दौरान जिले में 206 ऐसे परिसर और व्यावसायिक संस्थान चिन्हित किए गए थे, जहां अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी पाए गए थे।

इन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन लखनऊ अग्निकांड के बाद अब इस अभियान को और तेज कर दिया गया है।

**कोचिंग सेंटरों पर विशेष फोकस**

जीडीए की टीमों का फोकस इस बार खासतौर पर कोचिंग संस्थानों पर है। इसके अलावा अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और होटलों की भी जांच की जा रही है।

जिन 206 इमारतों को चिन्हित किया गया था, उनमें से 56 पर सीलिंग और सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया पहले से प्रस्तावित थी। मंगलवार को इन्हीं में से कई अवैध प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। शेष मामलों की रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेज दी गई है।

**सोसायटियों को जारी किए गए नोटिस**

प्राधिकरण ने उन सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भी नोटिस जारी किए हैं, जहां आरडब्ल्यूए का गठन हो चुका है।

सोसायटी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि फायर अलार्म, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम और आपातकालीन निकास मार्ग हर समय चालू और खुले रहें। किसी भी आपात स्थिति में जनहानि न हो, इसके लिए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

**दमकल विभाग को मिले 100 करोड़ रुपये**

शहर में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीडीए ने करीब 100 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इस बजट से फायर विभाग आधुनिक फायर फाइटिंग उपकरण खरीदेगा, जिससे बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली आग पर तेजी से काबू पाया जा सके।

# 'संविधान में ये नहीं लिखा', अभिजीत दिपके ने खोले बड़े राज! धूप, भूख-प्यास भी नहीं डिगा पाई 'कॉकरोचों' का हौसला

(जीएनएस)।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन चर्चा में बना हुआ है। यह विरोध प्रदर्शन ठएएळ वऋ पेपर लीक मामले और उन छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर किया जा रहा है जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी परेशानियों के बीच अपनी जान गंवाई। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

इस बीच प्रदर्शन स्थल पर सुविधाओं की कमी, लोगों की आवाजाही पर रोक और मीडिया कवरेज को लेकर भी बहस तेज हो गई है। उखढ से जुड़े अभिजीत दिपके (ॐीः३ ळ्र्ी) ने जंतर-मंतर पर मौजूद समर्थकों का आभार जताया और कहा कि कठिन हालात के बावजूद लोग आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

अभिजीत दिपके ने समर्थकों का जताया आभार

प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके ने वहां मौजूद लोगों का धन्यवाद करते हुए डल्लीर्ल्र्ी से कहा, "मैं यहां आए सभी लोगों को सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये सभी लोग मेरे भाई-बहन हैं। जो भी यहां खड़े हैं, उन्होंने इस आंदोलन को मजबूत बनाया है। कल दोपहर से ये लोग कड़ी धूप में खड़े रहे। इनके पास न पानी था, न खाना। इसके बावजूद ये पूरी रात यहीं डटे रहे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां मौजूद हैं। हम एक अच्छे मकसद के लिए लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होंगे।"

उनके बयान के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी और समर्थन को आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बताया गया। उन्होंने कहा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

जंतर-मंतर पहुंचने से लोगों को न रोका जाए

उन्होंने लोगों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने देने की मांग की।

अभिजीत दिपके ने कहा, "फिलहाल पुलिस से मेरी सबसे बड़ी अपील यही है कि लोगों को जंतर-मंतर आने से न रोका जाए। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से कई लोग यहां आना चाहते हैं। कल रात भी बड़ी संख्या में लोग बैरिकेड्स के बाहर खड़े थे। सिर्फ आम लोग ही नहीं, मीडिया के लोग भी बाहर मौजूद थे, लेकिन उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि किस लोकतंत्र में लोगों को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जाता है। इसी तरह किसी लोकतंत्र में मीडिया को किसी प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने से भी नहीं रोका जाना चाहिए। मेरी पुलिस से अपील है कि वह कानून और व्यवस्था के दायरे में काम करे। संविधान या कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मीडिया या लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक पहुंचने से रोका जाए।"

खाने, पानी और बिजली को लेकर भी चर्चा

प्रदर्शन के दौरान बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी सामने आया। बातचीत में यह सवाल उठाया गया कि प्रदर्शनकारियों को खाने, पानी और बिजली जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका उत्साह बना रहा।

प्रदर्शन से जुड़े लोगों का दावा है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद रातभर बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर मौजूद रहे। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य छात्रों के लिए न्याय की मांग करना है और इसी वजह से समर्थक लगातार डटे हुए हैं।

**राष्ट्रीय मीडिया पर लगाया आरोप**

मीडिया कवरेज को लेकर पूछे गए सवाल पर अभिजीत दिपके ने दावा किया कि राष्ट्रीय मीडिया इस प्रदर्शन को पर्याप्त जगह नहीं दे रहा है।

# लखनऊ अलीगंज अग्निकांड; सस्पेंड एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा-मुख्य जिम्मेदारी सीएफओ की

(जीएनएस)।

लखनऊः अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद निलंबित किए गए एफएसएसओ इंदिरानगर कमलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले के वास्तविक दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान कमलेंद्र ने सीएफओ को जिम्मेदार बताया है. कमलेंद्र ने सीएम योगी को पत्र लिखने के साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है.

मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र और वीडियो में कमलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि 22 जून को हुए इस हादसे ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया. घटना के बाद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एफएसएसओ का कार्यक्षेत्र सीमित होता है. उनका कहना है कि उनका दायित्व केवल स्थानीय स्तर पर निरीक्षण और रिपोर्टिंग का होता है, जबकि बिल्डिंग को फायर क्लीयरेंस देने और शहर की समग्र अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी चीफ फायर ऑफीसर (सीएफओ) की होती है.

कमलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जिस भवन को आवासीय उपयोग के

लिए स्वीकृति दी गई थी, उसका वर्षो से व्यावसायिक उपयोग हो रहा था. ऐसे में इसकी जानकारी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को होनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आग लगने के बाद राहत एवं बचाव कार्य में देरी और समन्वय की कमी देखने को मिली, जिसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

कमलेंद्र ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए, घटना के वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय और उचित मुआवजा दिलाया जाए.

बता दें कि, अलीगंज अग्निकांड के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. इनमें गौरव कुमार (अधिशासी अभियंता, कलेक्शन, जानकीपुरम), कमलेंद्र कुमार सिंह (एफएसएसओ, इंदिरानगर), अनिल कुमार (सहायक अभियंता) और प्रमोद पांडे (कनिष्ठ अभियंता) शामिल हैं. शासन ने इन अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश भी दिए हैं.

अब कमलेंद्र कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद मामले ने नया मोड़ लिया है. पत्र में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों को लेकर प्रशासनिक और फायर विभाग के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. वहीं, पीड़ित परिवारों और आम जनता की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में आखिरकार इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही किस स्तर पर तय होती है?